निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) में प्रारम्भा से 31 मार्च, 1997 तक स्थापना के लिए सवीकृत कुल 2333 परियोजनाओं में से 513 इकाइयां प्रचालन में थीं, कार्यन्वयन न कि जाने के कारण 1315 स्वीकृतियां रद्द/समाप्त की गई, 160 इकाइयों का बांड समाप्त किया गया और 200 इकाइयां कार्यन्वयन के विभिन्न चरणों में थीं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों में सम्मिलित हैं-विदेशी सहयोग, तकनीकी और विपणन समझौतें और क्रय वापसी प्रबंधों को अंतिम रूप देने में विलम्ब, बैंक वित्त की व्यवस्था या प्राप्ति में विलम्ब और संवर्धकों की रूचि की कमी आदि। चूंकि, ईपीजेड इकाइयां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कार्य करती हैं इसलिए मांग संरचना और अन्य गतिविधियों में अचानक परिवर्तनों के कारण भी उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है। क्षेत्र-प्रशासन उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करता आ रहा है।

विदेशी व्यापार में वृद्धि

4302. **श्री नागमणि**:

श्री ईशदत्त यादव:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन देशों के साथ भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) इस वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अपर्युक्त देशों और अन्य देशों के साथ व्यापार में और अधिक वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जिन मुख्य देशों के साथ भारत के व्यापार में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की गई उनका ब्यौरा और डालर के रूप में उक्त वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

देश	प्रतिशत वृद्धि	देश	प्रतिशत वृद्धि
बेल्जियम	8.62	हांकांग	1.42
फ्रांस	2.86	मलेशिया	5.98
यूनान	5.51	यू ए ई	4.03
आयरलैंड	26.98	इजरायल	36.38
इटली	5.04	मिस्र	102.74
पुर्तगाल	30.65	दक्षिण अफ्रीका	36.00
यू.के.	4.75	कनाडा	26.58
स्विटजरलैंड	105.82	यू एस ए	0.23
नेपाल	10.74	ब्राजील	18.60
आस्ट्रिया	12.89	रूस	8.99
चीन	34.08	सीआईएस के बाकी देश	34.04
		दक्षिण अमरिका	15.19

(ग) और (घ) बहुपक्षिय और द्विपक्षीय प्रयासों के तहत निर्यात संवर्धन के अनेक प्रयास किए गए हैं। व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय रूप से व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सतत् उपायों में हैं: संयुक्त आयोग की बैठकें के दौरान समय-समय पर विचार-विमर्श, द्विपक्षीय रूप से व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान और प्रमुख देशों में विशेषीकृत व्यापार मेंलों में भागीदारी।

सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्ता) के तहत द्विपक्षीय व्यापार के संवर्द्धन के लिए आयात शुल्कों को कम किया जा रहा है और गैर-टैरिफ अवरोधों के हटाया जा रहा है। मध्यवर्ती योजनाओं में उभरते व्यापार बाजारों जैसे लैटिन अमरीका, सीआईएस देशों और अफ्रीका के साथ हमारे, व्यापार पर एक विशेष दिशात्मक ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि व्यापार आंकड़ों से नोट किया गया है, भारत का निर्यात लैटिन अमरीका, अफ्रीका और सी आई एस देशों के साथ तीव्र गति से बढ़ रहा है।

फल और सब्जियां का निर्यात

4303. **श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा**:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से देश से फल और सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितने-कितने मूल्य के और कितनी-कितनी मात्रा में फल और सब्जियों का निर्यात किया गया;